भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2833

(6 अगस्त, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण-शहरी पलायन

2833. कुँवर सर्वेश कुमारः
श्री दुष्यंत चौटालाः
डॉ॰ वीरेन्द्र कुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में अवगत है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2025 तक भारत की आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या सरकार का विचार बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने और शहरी ग्रामीण पलायन को कम करने के उद्देश्य से देश में ग्रामीण संकुल विकसित करने का है;
(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2020 तक 300 ग्रामीण संकुलों की स्थापना करने का भी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ग्रामीण लोगों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं/प्रसुविधाएं प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों से उनका पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सुदर्शन भगत)

(क): जी, नहीं।

(ख)से (ड.): सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य क्लस्टर में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन को कम करना है। यह योजना अभी तैयार की जा रही है।